EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

The decks have been cleared by NCLT for the epic merger of Sony TV and Zee TV. This is a very positive indication and gives rise to a US$10-bn media entity. Both Sony and Zee together will account for an audience share of over 700 million in the TV and digital arena. Together the two entities post-merger will own over 70 TV channels, two video streaming platforms – ZEE5 and Sony LIV – and film studios – ZEE Studios and Sony Pictures Films India – with a market share of 26%.

However, the merger still has to see what will be the role of Punit Goenka in the merged entity. The merger still has to get past the final order regarding the promoters of Zee who have been barred from holding any position in the any listed company.

Another concern was Disney+ Hotstar lost 12.5 million subscribers due to the loss of sporting rights to Viacom. This shows that the Indian streaming market remains a difficult environment to achieve both scale and profitability. There have been rumours about Disney + Hotstar wishing to make an exit from the linear TV business from India and is scouting for potential buyers or have a JV with any company. If Disney makes an exit then Sony – Zee has the potential to take lead and emerge as the number one player in this segment. And if Goenkas are not able to hold any position then NP Singh of Sony may head the new entity. Singh is an old and experienced hand.

In another development he Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has issued a Consultation Paper on Review of Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services.

The authority has sought comments from stakeholders on the paper to address the issues raised in the new tariff order (NTO 3.0) issued in November, 2022.

This would address remaining issues pertaining to Tariff, Interconnection and Quality of Service of Broadcasting and Cable services, as identified by the stakeholders' committee and suggested by other stakeholders.

TRAI also released a consultation paper on regulatory mechanism for over-the-top (OTT) communication services, and selective banning of OTT services, seeking inputs from stakeholders.

The next few months will redefine new norms for OTT and address issues pertaining to broadcast and cable TV. I hope that this should improve things as we head to an election year in 2024.

(Manoj Kumar Madhavan)

*सोनी टीवी और जीटीवी के ऐतिहासिक विलय को एनसीएलटी की मंजूरी मिल गयी है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है और इसके चलते **10** बिलियन अमेरिकी डॉलर की मीडिया इकाई का जन्म हो रहा है। सोनी और जी दोनों मिलकर टीवी और डिजिटल क्षेत्र में **700** मिलियन से अधिक दर्शकों की हिस्सेदारी हासिल करेंगे। विलय के बाद दोनों इकाइयां मिलकर **70** से अधिक टीवी चैनलों, दो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म–जी **5** और सोनी लिव–और फिल्म स्टूडियो – जी स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया–की **26%** बाजार हिस्सेदार के साथ मालिक होंगे।*

हालांकि, विलय में अभी भी यह देखना होगा कि विलय वाली इकाई में श्री पुनित और श्री सुभाष चंद्रा की क्या भूमिका होगी। विलय को अभी भी जी के प्रमोटरों के संबंध में अंतिम आदेश मिलना बाकी है, जिन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कोई भी पद धारण करने से रोक दिया गया है।

*एक और चिंता की बात यह थी कि वायाकॉम के खेल अधिकार खोने के कारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने **12.5** मिलियन ग्राहक खो दिया है। इससे पता चलता है कि भारतीय स्ट्रीमिंग बाजार में पैमाने और लाभप्रदत्ता दोनों हासिल करने के लिए एक कठिन माहौल बना हुआ है। ऐसी अफवाहें हैं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार भारत से लीनियर टीवी व्यवसाय से बाहर निकलना चाहता है और संभावित खरीदारों की तलाश कर रहा है या किसी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम करने की कोशिश कर रहा है। यदि डिज्नी बाहर निकलता है तो सोनी – जी में बढ़त लेने और इस सेगमेंट में नंबर एक खिलाड़ी के रूप में उभरने की क्षमता है। और अगर श्री गोयनका कोई पद संभालने में सक्षम नहीं हैं तो सोनी के श्री एनपी सिंह नई इकाई के प्रमुख हो सकते हैं। श्री सिंह एक पुराने और अनुभवी व्यक्ति हैं।*

एक अन्य घटनाक्रम में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढ़ांचे की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

*प्राधिकरण ने नवंबर **2022** में जारी नये टैरिफ आदेश (एनटीओ **3.0**) में उठाये गये मुद्दों के समाधान के लिए हितधारकों से पेपर पर टिप्पणियां मांगी है।*

यह हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गये और अन्य हितधारकों द्वारा सुझाये गये प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ, इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता से संबंधित शेष मुद्दों का समाधान करेगा।

ट्राई ने ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए नियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध पर एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिसपर हितधारकों से इनपुट मांगा गया है।

*अगले कुछ महीने, ओटीटी के लिए नये मानदंडों को फिर से परिभाषित करेंगे और प्रसारण व केबल टीवी संबंधित मुद्दों का समाधान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे चीजों में सुधार होनी चाहिए क्योंकि हम **2024** में चुनावी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं।*

(Manoj Kumar Madhavan)